Azim Premji University

क्या शिक्षा सभी को बराबरी की ज़मीन पर रखती है?

गैर-स्कूली कार्य में भागीदारी और स्कूल के बाहर सीखने की सुविधाओं की उपलब्धता

Field Studies in Education | January 2019



क्या शिक्षा सभी को बराबरी की ज़मीन पर रखती है?

गैर-स्कूली कार्य में भागीदारी और स्कूल के बाहर सीखने की सुविधाओं की उपलब्धता

Research Group | Azim Premji Foundation

Contact : field.research@azimpremjifoundation.org

प्रस्तावना

बच्चों के सीखने के प्राथमिक साधन के रूप में तालीम के महत्त्व को अब नीति-निर्माता व अभिभावक दोनों ही स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसा कि अध्ययनों से पता चला है, स्कूल में सीखना महज़ शिक्षा व्यवस्था व स्कूल के स्तर पर मौजूद अनेक कारकों पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि यह व्यापक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संस्थाओं पर भी निर्भर होता है जिनके भीतर शिक्षा व्यवस्था व स्कूल काम करते हैं। बल्कि यह देखा गया है कि बच्चे स्कूल में कितना सीखते हैं इस पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि बच्चों के परिवार उनको स्कूल के बाहर सीखने में कितनी मदद कर सकते हैं और सीखने के कितने मौके उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर होती है वे अपने बच्चों को ज़्यादा बाहरी मदद कर पाते हैं। स्कूल व्यवस्था में बाज़ार के जरिए सुधार लाने के पैरोकार निजी व सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच सीखने के जिस अंतर की बात बार-बार करते रहते हैं वो आमतौर पर ऐसी स्थितियों के अन्तर से ही पैदा होती है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण भारत समेत दुनिया भर में हुए तमाम शोधों में मिलते हैं जो यह दिखाते हैं कि विद्यार्थियों के लक्षणों में समायोजन करने के बाद यह अंतर बहुत ही मामूली हो जाता है।[1]

हाल ही में किए गए एक ज़मीनी अध्ययन में हमने कुछ ऐसे तरीकों की पड़ताल की जिनसे बाहरी कारक अप्रत्यक्ष रूप से स्कूली प्रक्रियाओं में भाग लेने की बच्चों की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन ग्रामीण भारत में स्कूल चयन पर किए गए एक बड़े शोध[2] पर आधारित था जिसमें 4 राज्यों के 10 ज़िलों के 121 सरकारी व कम फीस वसूलने वाले निजी स्कूल और 1210 अभिभावक शामिल थे। इस शोध में शामिल कुल बच्चों में आधे से कुछ ही अधिक बच्चे (51 फीसदी) सरकारी स्कूलों में जाते हैं और बाकी निजी स्कूलों में। इन दोनों श्रेणियों के स्कूलों में जाने वाले बच्चों के परिवारों की सम्पत्ति के स्तर में अच्छा-खासा अन्तर था - सबसे कम सम्पत्ति वाले परिवारों के 71 फीसदी बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे थे जबकि सबसे ज़्यादा सम्पत्ति वाले परिवारों के मात्र 17 फीसदी बच्चे ही सरकारी स्कूलों में जा रहे थे।

1. ओईसीडी, 2016, पीसा 2015 रिज़ल्ट्स (वॉल्यूम II): पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेज़ फ़ॉर सक्सेसफुल स्कूल्स, ओईसीडी प्रकाशन, पेरिस; विश्व बैंक, 2018, वर्ल्ड डेवलपमेन्ट रिपोर्ट 2018: लर्निंग टू रियलाइज़ एजुकेशन्स प्रॉमिस, वाशिंगटन, डीसी: वर्ल्ड बैंक; शुडगर, ए. व क्विन, ई., 2012, 'रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट स्कूलिंग एंड अचीवमेंट: रिज़ल्ट्स फ़्रॉम रूरल एंड अर्बन इंडिया', इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रिव्यू, 31: 376-390; करोपाडी, डी. डी., 2014, 'डज़ स्कूल च्वॉएस हेल्प रूरल चिल्ड्रन फ़्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन्स?', इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 49(51), 46-53।

2. शोध समूह, 2018, स्कूल च्वॉएस इन लो-इनफॉरमेशन एनवायरमेन्ट: ए स्टडी ऑफ़ पर्सेप्शंस एंड रियल स्टेट, अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन।

1. सीखना और काम करना

इस अध्ययन में अभिभावकों से पूछा गया कि स्कूल के बाहर स्कूल से जुड़े कामकाज के अलावा बच्चे किस तरह के काम करते हैं। तालिका 1 में स्कूलों के प्रकार और जेण्डर के आधार पर उनके बच्चे क्या करते हैं इस बारे में अभिभावकों की प्रतिक्रिया को दिखाया गया है। इन प्रतिक्रियाओं में प्रत्येक श्रेणी में सरकारी व निजी स्कूलों में जाने वाले बच्चों के बीच और साथ ही लड़कों व लड़कियों के बीच अन्तर दिखाई देता है। सरकारी स्कूल जाने वाले 38 फीसदी बच्चों की तुलना में निजी स्कूल जाने वाले महज़ 25 फीसदी बच्चे ही किसी किस्म का गैर-स्कूली काम करते थे।

सरकारी व निजी दोनों ही तरह के स्कूलों में जाने वाले बच्चों में गैर-स्कूली कामकाज करने में लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में ज़्यादा था। हालाँकि सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के मामले में यह अन्तर अमूमन 10 फीसदी अंक के साथ कहीं ज़्यादा था।

तालिका 1: स्कूल के घंटों के बाहर गैर-स्कूली काम में व्यस्त बच्चे (% में)

	सरकारी			निजी		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
घरेलू कामकाज	25	38	31	16	23	19
दूसरे गैर-स्कूली कामकाज	9	6	7	7	4	6
कोई काम नहीं	66	56	62	77	73	75

जब इन आँकड़ों का विश्लेषण परिवार की सम्पत्ति के सन्दर्भ में रख कर किया गया तो सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों में गैर-स्कूली कामकाज के अनुपात में कोई खास उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला। लेकिन निजी स्कूल जाने वाले बच्चों में परिवार की आर्थिक हैसियत में बढ़ोतरी के साथ-साथ गैर-स्कूली कामकाज के अनुपात में कमी देखी गई।

2. स्कूल के बाहर सीखना

अभिभावकों से यह भी पूछा गया कि वे अपने बच्चों को स्कूल के अलावा सीखने में किस तरह की मदद मुहैया करा पाते हैं। इस सवाल के जवाब में सरकारी व निजी स्कूलों में जाने वाले बच्चों के अभिभावकों के बीच काफी अंतर दिखा। तालिका 2 में सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों को स्कूल के बाहर सीखने में मिलने वाली मदद के अंतर को दिखाया गया है। निजी स्कूल जाने वाले बच्चों के 65 फीसदी अभिभावकों ने कहा कि अभिभावकों द्वारा की जाने वाली देखरेख स्कूल के घंटों के बाद सीखने में बच्चों की मदद करने के तीन सबसे बड़े तरीकों में एक था। सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के मामले में महज़ 50 फीसदी अभिभावकों ने ही यह

जवाब दिया। निजी स्कूल के बच्चों के अभिभावकों के लिए स्कूल के बाहर मिलने वाली मदद का एक और महत्त्वपूर्ण स्रोत था भुगतान देकर लिया जाने वाली ट्यूशन। इस श्रेणी के 18 फीसदी अभिभावकों के लिए यह बाहरी मदद के तीन सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक था। सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों में यह अनुपात महज़ 5 फीसदी ही था। इसके उलट, स्कूल के बाहर बच्चों को किसी तरह की मदद कर पाने में अभिभावकों की अक्षमता का अनुपात निजी स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों (16 फीसदी) की तुलना में सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों में कहीं ज़्यादा था (35 फीसदी)।

तालिका 2: बच्चों को स्कूल के बाहर सीखने में मदद की उपलब्धता (% में)

	सरकारी	निजी
अभिभावकों द्वारा देखरेख	50	65
परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा देखरेख	17	15
भुगतान देकर लिया गया ट्यूशन	5	18
कोई मदद नहीं	35	16

तालिका 3 यह दिखाती है कि किस तरह परिवार की सम्पत्ति के अनुसार बच्चों को स्कूल के बाहर सीखने में मदद कर पाने की क्षमता और भुगतान देकर ट्यूशन लेने की क्षमता में अंतर आता है।

तालिका 3: परिवार की आर्थिक हैसियत के अनुसार (मुख्य मापदण्डों के संदर्भ में) स्कूल के बाहर सीखने में समर्थन देने की क्षमता (% में)

		सबसे गरीब 20%	सबसे अमीर 20%
भुगतान देकर ट्यूशन लेना	सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चे	4	18
	निजी स्कूल जाने वाले बच्चे	12	29
कोई मदद करने में अक्षम	सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चे	46	19
	निजी स्कूल जाने वाले बच्चे	14	10

परिवार की आर्थिक स्थिति में बेहतरी के साथ-साथ बच्चों को स्कूल के बाहर सीखने में मदद कर पाने की परिवार की अक्षमता में कमी आती देखी गई। हमारे शोध के नमूने में सबसे गरीब परिवारों के दो-तिहाई से भी ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और उनमें महज़ 4 फीसदी को ही भुगतान देकर ट्यूशन जैसी मदद मिलती है। दूसरी तरफ, सबसे समृद्ध परिवारों के 80 फीसदी से भी ज़्यादा बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं और उनमें से 29 फीसदी को ट्यूशन की मदद मिलती है। इसी तरह, सबसे गरीब परिवारों के जो 71 फीसदी बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं उनमें से 46 फीसदी को स्कूल के बाहर सीखने में कोई मदद नहीं मिलती जबकि सबसे अमीर परिवारों में निजी स्कूल जाने वाले 83 फीसदी बच्चों में से महज़ 10 फीसदी ही हैं जिनको स्कूल के बाहर सीखने में कोई मदद नहीं मिलती।

निष्कर्ष

बाज़ार-आधारित उपाय अकसर स्कूल से बाहर के सामाजिक-आर्थिक कारकों को या तो कम करके आँकते हैं या पूरी तरह अनदेखा ही कर देते हैं। जैसा कि हमारा अध्ययन बताता है, स्कूल में सीखने की प्रक्रियाओं में बच्चे किस हद तक भागीदारी कर सकते हैं उसमें ये कारक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इनमें से एक कारक, जो भारत में खासतौर से ग्रामीण इलाकों में और सामाजिक-आर्थिक तौर पर कमज़ोर तबकों में बहुत आम है वह है गैर-स्कूली कामकाज में बच्चे की भागीदारी। इसमें घरेलू कामकाज और परिवार की आय को बढ़ाने वाले मज़दूरी के काम दोनों शामिल हैं। इस कारक के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच सीखने के वातावरण की भिन्नता पैदा हो जाती है। हमारे अध्ययन में इसकी झलक इस तथ्य में मिलती है कि सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के गैर-स्कूली कामकाज करने की संभावना निजी स्कूल जाने वाले बच्चों की तुलना में ज़्यादा होगी। इसके अलावा, जैसा कि अपेक्षित है इस मामले में लड़कियों की स्थिति ज्यादा चिंतनीय रही है।

एक दूसरा कारक जो भारत में बहुत आम हो गया है वह है स्कूल के बाहर ट्यूशन की शक्ल में मिलने वाली मदद। भारत में निजी ट्यूशन की परिपाटी पर हुए अध्ययनों से पता चला है कि निजी ट्यूशनों की संख्या और उस पर किए जाने वाले खर्च दोनों ही मामलों में बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने वाले अभिभावक आगे हैं।[3]
इस तरह की जानकारियाँ हमें यह सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं कि क्या निजी ट्यूशन निजी स्कूल जा रहे बच्चों को पहले से ही उपलब्ध सामाजिक व आर्थिक 'सुविधाओं' को और भी मजबूत करते हैं। अभिभावकों की आर्थिक हैसियत के चलते इस तरह के संसाधनों तक ज़्यादा पहुँच से पता चलता है कि किस तरह निजी ट्यूशन शिक्षा व्यवस्था में विभेदों को पैदा करने व उनको गहरा करने का एक और जरिया हो सकते हैं। सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ एक और असुविधा यह है कि उनके अभिभावकों में स्कूल के बाहर सीखने में कोई प्रत्यक्ष मदद देने की या देखरेख करने की क्षमता भी सीमित होती है।

एक दूसरे स्तर पर देखें तो निजी स्कूलों में जाने वाले बच्चों के मामले में आमतौर पर भुगतान के बदले ट्यूशन के ऊँचे स्तर से निजी स्कूलों की कथित बेहतर गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं। जैसा कि एक अन्य अध्ययन में बताया गया है, "अगर सरकारी स्कूलों से 'असंतुष्टि' के चलते अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने लगें तो फिर अब अपने बच्चों को निजी स्कूल भेजने वाले अभिभावक उनको ट्यूशन पर क्यों भेज रहे हैं? इस प्रवृत्ति का सबब उनकी ऊँची आकांक्षाएँ हैं या स्कूलों में भरोसे की कमी?"[4]

कुल मिला कर, यह अध्ययन दिखाता है कि किस तरह व्यापक सामाजिक व आर्थिक असमानताएँ स्कूल व्यवस्था में भागीदारी कर पाने की बच्चों की संभावना में अंतर पैदा करती हैं। इस अध्ययन में एक स्तरीकृत स्कूली व्यवस्था में अंतर्निहित उन संभावित गैर-बराबरियों का भी पता चलता है और साथ ही यह भी कि अगर स्कूल व्यवस्था की गुणवत्ता के मसले पर ढांचागत स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस तरह की गैर-बराबरियाँ और भी गहरी हो सकती हैं।

---

4. आज़म, एम., 2016, 'प्राइवेट ट्यूटरिंग: एविडेंस फ़्रॉम इंडिया', रिव्यू ऑफ़ डेवलपमेन्ट इकोनॉमिक्स, 20(4), 739-761।

5. बैनर्जी, आर. और वाधवा, डब्ल्यू., 2013, 'एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल इन इंडिया: इनवेस्टिगेटिंग द इमप्लिकेशंस ऑफ़ स्कूल प्रोविज़न एंड सप्लीमेंटल हेल्प, इंडिया इंफ्रास्ट्रकचर रिपोर्ट 2012: प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन (पृ. 52-63), नई दिल्ली, भारत: राउटलेज।





Azim Premji University

Pixel Park, PES Campus, Electronic City, Hosur Road
Bangalore 560100

080-6614 5136
www. azimpremjiuniversity.edu.in

Facebook: /azimpremjiuniversity **Instagram:** @azimpremjiuniv **Twitter:** @azimpremjiuniv